नगरीय विकास मंत्री ने हाऊसिंग बोर्ड की पांच नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की

बूंदी, बारां, बाड़मेर, धौलपुर और उदयपुर में विकसित की जाने वाली इन योजनाओं के 667 नए आवास बनाए जाएंगे : झाबर सिंह खर्रा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की बहुप्रतीक्षित 5 आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ किया। प्रदेश में बूंदी, बारां, बाड़मेर, धौलपुर और उदयपुर में इन योजनाओं में कुल 667 आवास/फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। मंत्री खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है। उल्लेखनीय है कि मई माह में ही मण्डल ने 427 आवासों की 5 आवासीय योजना जयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर में शुरु की थी।

मंत्री खर्रा ने बताया कि बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास तैयार होंगे, जिनकी लागत 7 लाख 80 हजार से शुरू होगी। इसी तरह बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास बनेंगे, जिनकी लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ होगी। बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास तैयार होंगे, जिनकी लागत 8 लाख 61 हजार से शुरू होगी।

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की 5 आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ किया।

धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी-3) आय वर्ग के लिए 64 फ्लैट्स बनेंगे, जिनकी लागत 12.45 लाख रु. होगी। उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी-3) आय वर्ग के लिए 142 फ्लैट्स बनेंगे, इनकी लागत 11 लाख 68 हजार से शुरू होगी।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है।

समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी शिरकत की। गोदारा ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए आज भी पहली पसंद है।

- राजस्थान सरकार दे रही हर वर्ग को सम्मानजनक और आधुनिक आवास का अवसर : यूडीएच मंत्री
- आवास का सपना साकार करने के लिए हाऊसिंग बोर्ड आमजन की पहली पसंद : सुमित गोदारा

उन्होंने मण्डल की योजनाओं की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए बीकानेर शिवबाड़ी में भी नवीन आवासीय योजनाओं को शुरू करने की मांग की।

समारोह में आवासन मण्डल के अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि, आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, सचिव डॉ. अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टीएस मीना, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजस्थान में बड़े स्तर पर विकसित हो रही अन्न भण्डारण क्षमता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के मार्ग पर बढ़ रहा प्रदेश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। लेकिन मौसम की बेरूखी और भण्डारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भण्डारण क्षमता विकसित की जा रही है।

'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भण्डारण हेतु 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के

50 एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

योजना के अंतर्गत अन्न भण्डारण हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजन का लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के घोषित 100 गोदामों में से 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनमें से 24 गोदामों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 की ही बजट घोषणा के अंतर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों में से 47 गोदामों तथा 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों में से 47 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत घोषित 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 82 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन गोदामों को प्राथमिकता से किराये पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नैफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भण्डारण हेतु किराये पर दिये जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई है।

- इस सुविधा से किसानों की चिन्ता मिटेगी, अन्न की बर्बादी रूकेगी और पैक्स की होगी आय

नये गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध होने से अनाजों की ढुलाई में आने वाली लागत भी कम होगी। वहीं, नये भण्डारणों के निर्माण से अनाज की बर्बादी रूकेगी और गोदामों के किराए से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय भी बढ़ेगी।

अमानक खाद, बीज और दवाई से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से हो : किरोड़ीलाल

केन्द्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह व उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा से की कानूनी प्रावधान करने की मांग

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अमानक खाद, बीज व दवाई के दुष्प्रभाव से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करने का कानूनी प्रावधान करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि इससे उपयोग से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई भी कंपनियों से ही हो। अमानक उत्पादकों से किसानों का उत्पादन तो कम होता ही है, जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है। जब तक किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई कंपनियां नहीं करेगी तब तक इस ठगी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगेगी। किरोड़ीलाल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर अमानक खाद, बीज व

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।

पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी, जिस पर वे मुहर लगा चुके हैं। किरोड़ी ने इस प्रस्तावित कानून में किसानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा घटिया उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से वसूलने का प्रावधान जोड़ने की मांग की है। इस तरह की मांग उठाने वाले किरोड़ी किसी भी प्रदेश के पहले कृषि मंत्री हैं। किरोड़ी ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के संज्ञान में आया था कि सोयाबीन में नकली दवाई डालने से किसानों की फसल नष्ट हो गई। इसे बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की अनुशंसा पर इस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में अमानक उत्पाद बनाकर किसानों को ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ 29 मई से अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

- इस तरह की मांग उठाने वाले किरोड़ी किसी भी प्रदेश के पहले कृषि मंत्री

ई-रिक्शा से स्टंट कर पुलिस को चुनौती देने वाला गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने थाना विद्याधर नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर सोशल मीडिया पर ई-रिक्शा से खतरनाक स्टंट करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। और साथ ही ई-रिक्शा भी जब्त किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मनीष अग्रवाल ने बताया कि सीएसटी ने थाना विद्याधर नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर सोशल मीडिया पर ई-रिक्शा से खतरनाक स्टंट करने वाले ई-रिक्शा चालक फरदीन कुरैशी निवासी बिलाल मस्जिद के पास आरके होटल भट्टा बस्ती को गिरफ्तार किया है। जो ई-रिक्शा चलाता है। आरोपित फरदीन लगातार स्टंट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। स्टंटबाजी के दौरान वह आमजन की जान को खतरे में डाल रहा था। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से स्टंट करने में प्रयुक्त ई-रिक्शा भी जब्त कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसका मकसद सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच का प्रयास किया तो पुलिस ने शहीद स्मारक पर रोका

प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव शीघ्र करवाने की मांग

जयपुर (कासं)। राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायतीराज चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को जयपुर में राजभवन कूच का प्रयास किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एम.आई. रोड स्थित शहीद स्मारक पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए।

- पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी जवानों से नहीं उलझे, वहीं सड़क पर शांति से बैठकर नारेबाजी की

इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में स्वराज बचाओ रैली, पंचायत और निकाय चुनाव करने की मांग, निकाय पंचायत चुनाव में दो बच्चों का नियम हटाने जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लहराई।

कांग्रेस के पैदल मार्च को देखते हुए शहीद स्मारक के बाहर पुलिस ने तगड़े बंदोबस्त किए थे और अतिरिक्त

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरीय और पंचायतीराज चुनावों की मांग करते हुए जयपुर में रैली निकाली।

पुलिस फोर्स तैनात की थी। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस के साथ उलझने का प्रयास नहीं किया और शांति के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठे रहे।

इसके बाद राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शीघ्र कराने सहित कई अन्य मांगों का लेकर अपनी बात रखी। निकाय-पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान का ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया।

इससे पहले प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैदल मार्च को पीसीसी मुख्यालय के बाहर से रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता चरखा कातते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर निकाय पंचायत चुनाव को लेकर उनके योगदान को याद करते हुए अपनी अपनी बात रखी।

सरकारी कॉलेज को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने की मांग

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय को नवनिर्मित स्वयं के भवन में स्थानांतरित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।

सराफ ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय को नवनिर्मित स्वयं के भवन में स्थानांतरित किए जाने की ओर आकर्षित किया था। अब पुनः इस पत्र के माध्यम से इस बाबत आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2013 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जयपुर में नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया था। उस समय क्योंकि महाविद्यालय हेतु स्वयं का भवन नहीं था, इसलिए इस महाविद्यालय को गांधी सर्किल जेएलएन मार्ग स्थित राजा राम देव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 09 कमरों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान जब में उच्च शिक्षा मंत्री था तो इस राजकीय महाविद्यालय जयपुर को 6 मई 2015 को स्वयं के भवन के लिए 27876 वर्ग मीटर भूमि राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आवंटित की गई एवं महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु 100 करोड रुपए का बजट आवंटित किया। गया जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 38 करोड रुपए जारी किए गये। जिससे महाविद्यालय भवन के लिए नींव, बेसमेंट एवं प्लिंथ लेवल तक 9.50 करोड रुपए खर्च किए गये। तत्कालीन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा फरवरी 2022 में एक नया प्लान 355 करोड रूपये का लाया गया। जिसका नाम महात्मा गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस कर दिया। जिसमें 100 करोड रुपए राजकीय महाविद्यालय जयपुर के स्वयं के भवन हेतु प्रावधान किया गया।12 वर्षों से संचालित राजकीय महाविद्यालय जयपुर में वर्तमान में लगभग 3000 विद्यार्थी अध्यनरत है जिसमें बी.बी.ए,बी.सी.ए, एम.बी.ए, स्नातकोत्तर भूगोल, प्राणी शास्त्र, संस्कृत एवं बी.ए, बी.एस.सी बी.कॉम कंप्यूटर साइंस जैसे पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जा रहे हैं।

सांसद सी.पी. जोशी ने नई अफीम नीति पर दिए सुझाव

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में वर्ष 2025-26 की नई अफीम नीति पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक में चितौडगढ़ सांसद सी.पी.जोशी भी शामिल हुए। सांसद जोशी ने अफीम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव रखे और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अफीम किसान हमारी अर्थव्यवस्था और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। इसलिए अफीम नीति को भी इसी भावना से किसानों के हित में और अधिक पारदर्शी व व्यावहारिक बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। सांसद जोशी ने सुझाव दिया कि, अफीम नीति को सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में ही घोषित किया जाये, जिससे की किसानों को खेत तैयार करने का पर्याप्त समय मिल पाये तथा इसके साथ लाईसेंस के लिये पात्र सभी किसानों के नाम अफीम नीति घोषित होते ही ऑनलाईन प्रदर्शित होनी चाहिए। लाईसेंस भी किसान के पास ऑनलाईन ही पंहुच जाना चाहिये।

अफीम की खेती से जुड़े सभी प्रकार के कार्यो में कोई गड़बड़ी या अनियमितताएं नही हो, इसके लिये प्रभावी मोनिटरिंग हो।

गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए। विभिन्न प्रकार से होल्ड किये गये लाईसेंस को 0 प्रतिशत पर बहाल किया जाये।

8/29 में आवश्यक संशोधन किया जाये, जिससे इसका दुरूपयोग ना हो पाऐं। ऐसे किसान जो पूर्व के वर्षों में लाइसेंस हेतु पात्र थे किन्तु किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रह गए थे उन्हें वर्ष 2025-26 में लाइसेंस प्रकिया में शामिल किया जावे।

मृतक नामांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम करने की आवश्यकता है। अफीम लाइसेंस वितरण एवं तौल प्रकिया की तारीख को 15 दिवस पूर्व ही ऑनलाइन कर दिया जावे जिससे किसान घर से ऑनलाइन तारीख देख सके जिससे अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।

द्रव्यवती नदी से सटी 3 हैक्टेयर भूमि पर 28 हजार पेड़-पौधे लगाकर किया कायाकल्प

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप जे.डी.ए. प्रशासन करवा रहा मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण

जयपुर (कासं)। अमानीशाह नाले को द्रव्यवती नदी में तब्दील करने के साथ-साथ जेडीए प्रशासन इससे सटी 3 हैक्टेयर उजाड़ जमीन पर मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण करवाकर कायाकल्प करने में जुटा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार द्रव्यवती नदी सेक्टर 5 और 35 में जेडीए प्रशासन करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण करवा रहा है। इसके लिए फर्म मैसर्स छोटेलाल वीरेंद्र कुमार जैन को ठेका दिया गया है।

इस फर्म ने महज 1 माह के कम अंतराल में इस जमीन पर उगी जंगली झाड़ियों और घासफूस को हटाकर 28 हजार से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए है। जिनमें 10 फीट ऊंचाई के 8105 तथा पांच व तीन फीट ऊंचाई के 18500 पौधे शामिल हैं। इसके अलावा फूलों की बेल भी शामिल है।

बताया जा रहा है कि जेडीए प्रशासन ने सघन वृक्षारोपण के लिए 4 माह का समय इस फर्म को दिया था, परंतु ठेकेदार ने 100 से ज्यादा कुशल बागवान प्रतिदिन लगाकर इस काम को महज एक माह के अंतराल में पूरा कर लिया। द्रव्यवती नदी

जयपुर की द्रव्यवती नदी से सटी जमीन पर भी जंगली झाडियों को हटाकर जेडीए ने यहां सघन वृक्षारोपण किया है।

के किनारे बाकायदा सीमेंट के पोल, तारबंदी और रैलिंग लगाई गई है। इन तमाम पौधों का 2 वर्ष के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी फर्म को सौंपी गई है।

बताया जा रहा है कि जल्द ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कालवाड़ रोड स्थित गजाधरपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के नजदीक भी मियावाकी पद्धित से 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का काम किया जाएगा इसके लिए मौके पर जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर्स द्वारा भूमि समतलीकरण और साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।बताया जा रहा है कि जेडीए प्रशासन ने यहां पर एक आवासीय योजना भी कई वर्षों पहले विकसित की थी, परन्तु वहां पर लोगों के शिफ्ट नहीं होने का मुख्य कारण यह क्षेत्र उजाड़ लगना और सीवरेज की बदबू थी। परंतु अब यहां सघन वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण दूर करने की कयावद शुरु हुई है।

सिंधी समाज ने विभाजन का दर्द सहा पर संस्कृति को जीवित रखा : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सिंधी समाज हमेशा से पुरुषार्थी रहा है। उन्होंने कहा कि देश सहित अयोध्या के विकास में सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिंधी समाज देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब समाज के बच्चें प्रशासनिक सेवाओं में भी आगे आ रहे है यह गर्व का विषय है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संत साई नितिन राम और सिंधु सेवा समिति (रजि.) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमृत राजपाल ने अयोध्या में प्रभु झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रभु झूलेलाल की आरती के साथ दीप प्रज्ज्वलन करके 73 वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव का शुभारम्भ किया।

समारोह का संचालन ट्रस्ट के संरक्षक गिरधारी चावला और महामंत्री नरेन्द्र क्षेत्रपाल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवनानी का प्रभु झूलेलाल की प्रतिमा, शॉल ओढाकर व पुष्प गुच्छ व पाखर भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर देवनानी ने स्नातक और परास्नातक में

- कोहिनूर पैलेस में दिखी सिंधु संस्कृति की झलक, अयोध्या की पावन भूमि पर 73वाँ झूलेलाल महोत्सव
- देवनानी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा को देखा और महाना से मुलाकात की

उत्कृष्ट युवाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया।

73 वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव में एक शाम सिंधियत के नाम में अंतर्राष्ट्रीय गायक जतिन उदासी व ज्योति पहलाजानी ने सिंधी गौतों से सर्व समाज का मन मोह लिया। देवनानी ने कहा कि अयोध्या एक नगर के साथ आध्यात्म और मर्यादा की पावन स्थली है। यहाँ भगवान श्रीराम ने सत्य और त्याग का संदेश दिया, वहीं प्रभु झूलेलाल ने समाज को साहस, न्याय और एकता की राह दिखाई।